



दुर्गम बनाने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, आप मेहनत करके कामयाब हो गए तो दुर्गमनों की लाइन स्वयं लग जाएगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

जनादेश को खुले दिल से स्वीकार करें

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों की समानता उत्तर कोरिया, रूस और चीन के 'चुनावों' से करते हुए जनादेश का अपमान किया है। इन तीनों देशों में कितना लोकतंत्र है? है भी या नहीं? क्या भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता यह नहीं जानते? पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में एक खतरनाक चलन देखा जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। कुछ राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद अपने प्रयासों में कमी को स्वीकार करने के बजाय सारा दोष चुनाव आयोग, ईवीएम और मतदाताओं पर डाल देते हैं। वे यह प्रदर्शित करते हैं कि 'हम अपनी जगह सही हैं, गलती इस व्यवस्था की है।' वे जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतते हैं तो उन्हें ईवीएम ठीक लगती है, सबकुछ ठीक लगता है। जब राजस्थान में चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में खोट नजर आता है! जब तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हार जाते हैं तो सब जगह गड़बड़ नजर आती है! ऐसे ही स्वर बिहार चुनाव के बाद सुनाई दे रहे हैं। इस जनादेश को खुले दिल से क्यों नहीं स्वीकार करते? यह कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता कि 'हमें जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, हमारे प्रयासों में कोई कमी रही होगी, अब भविष्य में अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे।' उ. कोरिया, रूस और चीन में सरकार की जप-सी भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया जाता। किम-जोंग-उन के कारनामे दुनियाभर में मशहूर हैं। सारी दुनिया जानती है कि पुतिन के कई राजनीतिक विरोधी एक-एक कर गायब हो चुके हैं। चीन में शी जिनिपिंग के खिलाफ बयान देकर कोई व्यक्ति कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है? वहीं, बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए घोर अपातिजनक शब्दों का प्रयोग किया था! अगर कोई व्यक्ति ऐसे शब्द उ. कोरिया, रूस या चीन में रहते हुए उनके राष्ट्राध्यक्षों के संबंध में बोल दे तो उस पर ऐसा दुर्भाग्य टूट पड़ेगा, जिसकी यह कल्पना नहीं कर सकता।

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर बड़े-बड़े विश्लेषक हैरान हैं। कुछ तो यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि राजग की इतनी सीटें आ सकती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं-न-कहीं बहुत बड़ी साजिश हुई है। हालांकि इन नतीजों को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। जनता ने अनेक बार विश्लेषकों को चौंकाया है। कई विश्लेषकों के साथ यह समस्या है कि वे तटस्थ नहीं हैं। वे किसी नेता, पार्टी, राजनीतिक विचारधारा की ओर झुकाव रखते हैं। कई तो आज भी तीस-चालीस साल पुराने समीकरणों को मौजूदा हालात में फिट करने की नाकाम कोशिश करते हैं और नतीजे आने के बाद भ्रम फैलाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे अरसी और नख्बे के दशक में लोग अपनी-अपनी जातियों के उम्मीदवारों को ही वोट देते थे, उसी तरह आज देते होंगे। उनका खयाल है कि आज भी गांव-देहात की महिलाओं को चुनावी राजनीति की ज्यादा जानकारी नहीं है और वे अपने ससुर, जेट, पति आदि के कहने पर वोट देती हैं। कुछ नेताओं को यह भ्रम है कि वे लोकलुभावनी घोषणाएं कर देंगे तो जनता उन पर आखें मूंदकर विश्वास कर लेगी। अब सबके पास मोबाइल फोन है, जिस पर वे वूट्‌कियों में उन घोषणाओं की हकीकत जान सकते हैं। बिहार के मतदाताओं ने ऐसे विश्लेषकों और नेताओं के साथ ही एक मशहूर चुनावी रणनीतिकार को फेल कर दिया। प्रशांत किशोर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर खूब छाप रहे। कुछ लोग उन्हें बिहार का 'चाणक्य' तक कहने लगे थे। उनकी जन सुराज पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानतें जब्त करवा बैठे हैं! इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि चुनाव में जनता से बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं होता है। अगर जनता किसी को विजयभी का आशीर्वाद देना चाहे तो कोई गठबंधन और रणनीतिकार उसे नहीं रोक सकता।

ट्वीटर टॉक



भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासी समाज की आवाज बनकर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा, आज भी जनजातीय अस्मिता के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो यह सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि उस स्वाभिमान का उत्सव था, जो सदियों से दबा था।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत



अंता की जनता-जनार्दन को हृदय से प्रणाम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपना अपार विश्वास जताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रमोद भाया जी को प्रचंड जीत दिलाई। यह जीत हर कांग्रेस कार्यकर्ता की तपस्या, समर्पण और अथक परिश्रम की जीत है। अंता की जनता ने अपने मत से न सिर्फ सत्य और सेवा को चुना, बल्कि भाजपा के सरकार के कुशासन और अहंकार पर करारा प्रहार भी किया है।

-गोविंद सिंह डोटसरा

प्रेरक प्रसंग



जिंदगी की असली जगह

एक दिन दर्शनशास्त्र के एक बुजुर्ग अध्यापक अपनी कक्षा में आए। उनके हाथ में एक खाली काँच का जार था। वे मुकुरार और बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें जिंदगी का एक छोटा-सा राज बताने आया हूँ। उन्होंने जार में बड़े-बड़े पत्थर डाल दिए। पूछा, क्या यह भर गया? सबने कहा, हाँ। फिर उन्होंने छोटे-छोटे कंकड़ उठाए और जार में डाल दिए। कंकड़ पत्थरों के बीच की जगह में समा गए। उन्होंने फिर पूछा, अब भर गया? सब बोले, हाँ, अब तो पूरा भर गया! अंत में अध्यापक ने रेत उठाई और जार में डाल दी। रेत हर छोटी जगह में फैल गई। उन्होंने फिर पूछा, और अब? कक्षा एक सुर में बोली, जी, अब तो पूरी तरह भर गया! अध्यापक ने जार को मेज पर रखा और धीमी आवाज़ में बोलेयह जार तुम्हारी जिंदगी है। इनमें पड़े बड़े पत्थर तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ें हैंतुम्हारा परिवार, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारा जीवनसाथी, बच्चे, सेहत और सच्चे रिश्ते। कंकड़ वे चीज़ें हैं जो जरूरी तो हैं, पर जीवन का आधार नहीं जैसे काम, घर, धन-दौलत। और रेत? रेत उन छोटी-छोटी बातों की निशानी है दैनिक उलझनें, छोटी चिंताएँ, दिखावा, गैर-जरूरी चीज़ें। अगर तुम पहले अपनी जिंदगी को रेत से भर लोगे, तो बड़े पत्थरोंयानी असली रिश्तों और खुशीके लिए कभी जगह ही नहीं बचेगी। इसलिएपहले उन चीज़ों को प्राथमिकता दो जो सब में मायने रखती हैं। परिवार के साथ बैठो, मुकुरारओ, सेहत का ध्यान रखो, और उन लोगों से प्यार करो जो तुम्हारे अपने हैं। बाकी सब चीज़ें? वे तो बस रेत हैं।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.) Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वगैरह, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त करें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उपायों की मांगला सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

एनडीए की 'सुनामी' को भांपने में क्यों फेल हुए एग्जिट पोल?

योगेश कुमार गोयल

मोबाइल : 9416740584

नीतियों, संस्था-शास्त्र और राजनीतिक सामाजिक रुझानों को समझने का दावा करने वाले एग्जिट पोल्स एक बार फिर बिहार के जनादेश के सामने बुरी तरह धराशायी हो गए। यह वही बिहार है, जहां जनता की राजनीतिक सूझबूझ देशभर में मिसाल मानी जाती है और इसी बिहार ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मतदाता का मन कागजों, ग्राफों और टीवी स्टूडियो की चर्चाओं से नहीं पढ़ा जा सकता। लगभग दो दर्जन एजेंसियों ने अपने-अपने अनुमानों की बोछार कर दी थी लेकिन नतीजों ने इनकी तथाकथित वैज्ञानिकता का मुखौटा एक झटके में उतारकर फेंक दिया। मतदान के बाद तमाम टीवी चैनलों पर जोर-शोर से दावे किए जा रहे थे कि इस बार तस्वीर साफ है, रुझान स्थिर हैं और रणनीति मजबूत है परन्तु असलियत यह थी कि वैज्ञानिक सैम्पलिंग के नाम पर केवल अनुमान बेचे जा रहे थे और इन अनुमानों का आधार जमीन से ज्यादा स्टूडियो-केंद्रित 'कॉल्लिनिजिटी' था।

हालांकि बिहार के दो चरणों वाले चुनाव में भारी मतदान ने यह संकेत पहले ही दे दिया था कि इस बार कुछ अलग ही लहर है लेकिन लहर कितनी प्रचंड होगी, इसे कोई भी एजेंसी अपने सर्वे में नहीं पकड़ सकी। 65 और 68 प्रतिशत की रिपोर्टें वोटिंग ने विश्लेषकों को जरूर सतर्क किया था लेकिन यह सतर्कता भी उस समय ध्वस्त हो गई, जब एग्जिट पोल्स ने लगभग एक जैसी थाली परोसी यानी एनडीए की जीत लेकिन सीमित मार्जिन के साथ। लगभग सभी 'पोल ऑफ पोल्स' ने एनडीए को 150 के आसपास और महागठबंधन को 80-90 सीटों तक टिका दिया, मानो मतदाता किसी स्थिर पैटर्न में वोट डालने गया हो। इन अनुमानित संख्याओं में न आत्मविश्वास झलकता था, न शोका की गंभीरता। यही नहीं, प्रतिष्ठित मानी जाने वाली एक्सिस माय इंडिया और टुडेज चाणक्य जैसी एजेंसियां भी उस भूचाल को भांप नहीं सकी, जिसने एनडीए को 200 से अधिक सीटों के साथ रिकॉर्ड बहुमत दे दिया। यह पराजय अनुमान की नहीं, समझ की थी और यह विफलता आंकड़ों की नहीं, पद्धति की थी, जो सवाल उठाती है कि क्या एग्जिट पोल्स विश्लेषण करते हैं या महज भविष्यवाणी का खेल खेलते हैं?



सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सभी एजेंसियों के बीच 'पोल डायरी' नाम की एकमात्र एजेंसी थी, जिसने एनडीए को 184-209 सीटों तक का अनुमान देकर राजनीतिक गलियों को चौकन्ना कर दिया था। उस समय इसे कई विशेषज्ञों ने 'आउटलायर' कहकर खारिज कर दिया था परंतु नतीजे आए तो वही आउटलायर सबसे सटीक साबित हुआ। महागठबंधन को 32-49 सीटों का उसका अनुमान भी वास्तविक परिणामों से मेल खा गया। यह सवाल और बढ़ा हो जाता है कि जब सारी एजेंसियां एक दिशा में झुकी हों और एक एजेंसी अलग दृष्टि दे रही हो, तब भी आखिर क्यों तथाकथित विशेषज्ञता उस एकमात्र भिन्न अनुमान को गंभीरता से नहीं लेती? जवाब स्पष्ट है कि एग्जिट पोल अब एक उद्योग है और उद्योग में जोखिम लेने की जगह कम होती है। सबको उसी लय में बोलना सुविधाजनक लगता है, जिसमें बहुमत की आवाज सुनाई देती है।

बिहार में एक्सिस ने 121-141, चाणक्य ने 148-172, भास्कर ने 145-160, पीपुल पल्स ने 133-159, मैट्रिज-आईएनएस ने 147-167 और लगभग हर एजेंसी ने 130 से 160 के बीच एनडीए को बांधकर रखा। महागठबंधन को इन्हीं एजेंसियों ने उदारता के साथ 75-110 सीटें सौंप दी, मानो राजनीतिक धुरीकरण, जातीय समीकरणों के पुनर्संयोजन, महिलाओं और युवाओं के मतदान पैटर्न जैसी वास्तविकताओं का कोई महत्व ही न हो। नतीजा? जमीन पर वोटर ने इन सारे अनुमानों को कागजी गणित साबित कर दिया। एनडीए जहां 200 सीटों से ऊपर निकल गया, वहीं महागठबंधन 35

के आसपास सिमट गया।

बिहार की राजनीति की जटिलता को समझ पाने में एग्जिट पोल्स की असमर्थता कोई नई बात नहीं है। 2010, 2015 और 2020 में भी वे लगातार विफल रहे। 2015 में जब नीतीश-लालू गठबंधन की प्रचंड जीत हुई थी जबकि सर्वे एजेंसियों ने इसके उलट एनडीए की बढ़त दिखाई थी। 2020 में जब लगभग हर सर्वे ने महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की थी, तब नतीजों ने एनडीए को 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पर पहुंचा दिया था। अब 2025 में जब एनडीए की सुनामी आई, तब उसे भी पढ़ने में लगभग सभी एजेंसियां एक बार फिर चूक गईं। आखिर चुनावी समाजशास्त्र में ऐसी क्या अंधी दीवार है, जो इन एजेंसियों को वास्तविकता से टकराने पर मजबूर कर देती है?

यह विफलता केवल बिहार तक सीमित नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और यहां तक कि लोकसभा चुनावों तक में एग्जिट पोल्स बार-बार चित्त होते आए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में तो लगभग हर एजेंसी ने एनडीए को 350-400 सीटों का आकाश छूता अनुमान दिया था जबकि भाजपा 240 सीटों पर रुक गई थी और एनडीए 292 पर। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल्स ने 150-170 सीटों की महायुति दिखा दी पर वास्तविक नतीजे 234 सीटों के विशाल बहुमत में तब्दील हो गए। झारखंड में अनुमान एनडीए का, नतीजा इंडिया ब्लॉक का; बंगाल में अनुमान त्रिशंकु का, नतीजा टीएमसी का; गुजरात में, तो क्या यह कहना गलत है कि एग्जिट पोल अब विश्लेषण का औजार नहीं बल्कि

नजरिया

ट्रम्प टैरिफ को भारत ने निष्प्रभावी कैसे किया?

आचार्य श्रीहरि

मोबाइल : 9315206123

डोनाल्ड ट्रम्प ने जब भारत पर अनावश्यक और भारी टैक्स लगाया था तब दुनिया की प्रतिक्रिया बहुत ही नकरात्मक थी और भारत को हतोत्साहित करने वाली थीं। दुनिया की समझ थी कि भारत ट्रम्प टैरिफ को झेल नहीं पायेगा, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी, उद्योग-फैक्टरियां बंद हो जायेगी, लोग बेरोजगार हो जायेंगे, बेरोजगार लोग सड़कों पर उतरेंगे और नरेन्द्र मोदी की सत्ता का संहार कर देंगे। नरेन्द्र मोदी की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह बेरोजगारों के आक्रोश का नियंत्रण कैसे करेंगे? सही भी यही था कि बेरोजगारी के नाम पर जेन जी आंदोलन दुनिया के कई हिस्सों में चर्चित रहा था, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सत्ता पलटने का माध्यम बन गया था। भारत के पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जेन जी ने अपना प्रभाव दिखाया था और अपने आंदोलन के तेज से जड़ जमायी हुई सरकार और सत्ता को उखाड़ फेका था। इसलिए भारत के सत्ता विरोधियों ने खुली घोषणा कर रखी थी कि नरेन्द्र मोदी अमेरिका के टैरिफ युद्ध में पराजित हो जायेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था का विध्वंस कर देंगे।

संयम सबसे बड़ा प्रतिकार होता है, हथियार होता है। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने संयम दिखाया था, जवाबी प्रतिक्रिया में उलझने से बचने का कार्य किया था और पहले देखो उसके बाद प्रतिक्रिया दो, फिर जवाबी कदम उठाओ की नीति अपनायी थी। निष्ठा प्रभाव को देखे ही कदम उठा लेना या फिर किसी टैरिफ युद्ध में उलझ जाना भी समझदारी की बात नहीं हो सकती है। डोनाल्ड ट्रम्प का गुस्ता, उनकी तुलनीक चाल में किन्ना दम है, यह देखना जरूरी था। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि ट्रम्प टैरिफ को निष्प्रभावी करने के लिए भारत को कोई खास नीतियां नहीं बनानी पड़ी, कोई उलझन पूर्ण परिस्थियां नहीं बनानी पड़ी, सावधानियां और धैर्य भारत के लिए वरदान साबित हुआ और भारत ने अपनी टैरिफ कूटनीति का लोहा मनवा लिया।

टैरिफ नीति अमेरिका और ट्रम्प के लिए भी घातक सिद्ध हुई, महंगाई बढ़ाने वाली और अर्थव्यवस्था को चैपट करने वाली आत्मघाती साबित हुई। ट्रम्प के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हो गया, महंगाई से लोग परेशान हो गये। ट्रम्प को टैरिफ प्रतिशत घटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ट्रम्प ने कांफें, केला, टमाटर, ग्रीक, जेनेरिक दवाओं सहित दो सौ से अधिक खाद्य वस्तुओं पर टैरिफ घटाई है। आम, अनार, चाय और जेनेरेटिक दवाओं पर टैरिफ घटने से भारत को लाभ होगा। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। ट्रम्प टैरिफ का किन्ना प्रभाव पड़ा भारत पर? इसका कोई सटीक आकलन



तो नहीं है पर यह कहा जा सकता है कि ट्रम्प के मंसूबे पूरे नहीं हुए, भारत विरोधियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, भारत के अंदर नरेन्द्र मोदी के विरोधियों के बगावत होने जैसी उनकी धारणाएं पूरी नहीं हुई। कहने का अर्थ यह है कि कोई हाहाकारी और बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन प्रक्रियाएं ठप नहीं हुई, उनकी उत्पादन प्रक्रियाएं टैरिफ युद्ध की पूर्व की तरह चलती रहीं। मजदूरों और तकनीकी समूहों को बेरोजगार होने की जरूरत नहीं पड़ी। औद्योगिक इकाइयों और मजदूर समूहों को यह मालूम था कि यह ट्रम्प का तुलनीक फरमान है, ट्रम्प की सनक है, चैंडराइट का कदम है जो थोड़े दिनों में खुद ही दम तोड़ देगा, खुद ही ध्वस्त हो जायेगा। अगर अमेरिका में कोई परेशानी होगी, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल असर पडा तो फिर अन्य मार्केट की ओर कदम रखना होगा। भारत सरकार ने बहुत ही सावधानी से खेल खेला। अमेरिका पर ध्यान देने की जगह अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सिर्फ अमेरिका ही एक बाजार नहीं है, अमेरिका के अलावा भी दुनिया में कई बाजार हैं, ऐसे भी अमेरिकी बाजार पर भारत का एकाधिकार नहीं रहा है, अमेरिका के बाजार पर चीन का एकाधिकार रहा है, कनाडा, ब्राजील और बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया की भी अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी है। भारत ने यूरोप के छोटे-छोटे देशों की ओर देखना शुरू कर दिया, अफ्रीका देशों में बाजार की अपार संभावनाएं हैं, जहां पर चीनी एक छत्र राज के सामने अपना प्रभाव जमाया जा सकता है और अपनी जगह बनायी जा सकती है, मिडिल इस्ट का बाजार भी महत्पूर्ण है, भारत पिछले कई सालों से पूर्व की ओर

देखो की नीति अपना रखी है।

नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प टैरिफ को निष्प्रभावी करने के लिए एक ऐसा ब्रम्हास्त्र खोजा जिसकी लोग कल्पना ही नहीं की थी। वह ब्रम्हास्त्र स्वदेशी का है। नरेन्द्र मोदी की समझ थी कि स्वदेशी के ब्रम्हास्त्र से डोनाल्ड ट्रम्प को पराजित किया जा सकता है, उनकी हेकड़ी को तोड़ा जा सकता है, उनकी चैंडराइट को बेअसर किया जा सकता है और भारत अपनी स्वतंत्र कूटनीति और राष्ट्रीयता का डंडा दुनिया के सामने बजा सकता है। नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील कर डाली, कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ और राष्ट्र को जीवत रखो। स्वदेशी का मंत्र अचूक है। स्वदेशी का आबादी वाला देश है। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है। पूरे यूरोप की आबादी से बड़ा तो हमारा उत्तर प्रदेश है। चीन भी हमारी आबादी के सामने पीछे है। इसलिए हमारे पास घरेलू बाजार की अपार संभावनाएं हैं। अगर स्वदेशी का अभियान सफल हो गया तो फिर कई अमेरिकी कंपनियों का ही नहीं बल्कि चीनी, जापानी, कोरियाई और यूरोपीय कंपनियों का बाजा बज सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार घरेलू मार्केट भी है। नरेन्द्र मोदी का स्वदेशी अभियान ने देशवासियों का ध्यान भी खींचा। देशवासी नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी अभियान से भी जुड़े। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर जोहो मेल को अपना लिया। जोहो मेल स्वदेशी मेल है जो गुराल, जमीन, याहू आदि को चुनौती दे रहा है। अमित शाह ने जैसे ही अपना जोहो मेल को सार्वजनिक किया

मनोरंजन का साधन बन चुके हैं?

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर एग्जिट पोल्स किस विज्ञान' पर चलते हैं? एजेंसियां दावा करती हैं कि वे वैज्ञानिक सैम्पलिंग, पिछले चुनावों के पैटर्न, जातीय-क्षेत्रीय वितरण, बुधवार गणना और वोट शेयर रूपांतरण मॉडल पर काम करती हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि यह डेटा कितने बूथों से लिया जाता है, कितने मतदाताओं से बात होती है, कौनसे अनुपात लागू किए जाते हैं, इन सबकी पारदर्शिता लगभग शून्य है। वैज्ञानिक मॉडल' की आड़ में यह उद्योग एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है, जहां अंदर क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता और बाहर सिर्फ अनुमान बेचा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सैंपलिंग से नतीजे निकाले नहीं जा सकते। दुनियाभर में चुनाव पूर्व सर्वे और एग्जिट पोल आम प्रचलन में हैं लेकिन वहां मैथडोलॉजी खुली होती है, डेटा उपलब्ध होता है और एजेंसियों का मूल्यांकन उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। भारत में इसके उलट, टीवी चैनल टीआरपी के लिए और सर्वे एजेंसियां कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्जिट पोल पेश करती हैं। इन्हें वास्तविकता से ज्यादा कथानक गढ़ने में रुचि होती है। कई बार राजनीतिक पक्षधरता, कई बार व्यावसायिक दबाव और कुछ मामलों में सेंसर की कमी जैसे बहाने इस उद्योग का स्थायी फॉर्मूला बन चुके हैं।

कुल मिलाकर, बिहार के 2025 के जनादेश ने एक बार फिर यह साबित किया है कि एग्जिट पोल्स मतदाता को पढ़ने का नहीं, मतदाता को प्रभावित करने का उपकरण बन चुके हैं। किसी भी लोकतंत्र में यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। जब टीवी चैनल और एजेंसियां मिलकर मतदाता के मन की थाह लेने के बजाय उसकी धारणाओं को दिशा देने में लग जाएं, तब उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने स्वाभाविक हैं। यह समय है कि भारत में एग्जिट पोल्स के लिए स्वतंत्र विधिक नियंत्रण, स्पष्ट पद्धति प्रकटीकरण, सैम्पलिंग मानक, पारदर्शिता नियम और जवाबदेही लागू की जाए। जब तक यह उद्योग अनुमानों की दुकान' बना रहेगा, तब तक उसका हर अनुमान एक जोखिम होगा और उसकी हर भविष्यवाणी लोकतंत्र को भ्रमित करने का माध्यम। हालांकि बिहार ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि यहां का मतदाता किसी भी 'पोल' से बड़ा है। 'पोल ऑफ पोल्स' विफल हुआ लेकिन जनता का पोल एकदम सही बैठा। यही बिहार की राजनीतिक चेतना की असली शक्ति है और यही लोकतंत्र की वह जीवंत धड़कन है, जिसे कोई सर्वे, कोई ग्राफ और कोई चैनल स्टूडियो कभी समझ नहीं पाएगा।

और सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने स्वदेशी जोहो मेल को अपना लिया है और मुझसे इस जोहो मेल पर संपर्क किया जा सकता है, संवाद किया जा सकता है वैसे ही जोहो मेल भारत में विख्यात हो गया, लाखों-करोड़ों ने जीमेल आदि विदेशी कंपनियों की जगह जोहो मेल को अपना लिया। जोहो मेल की बढ़ती साख और बढ़ता प्रसार अमेरिकी कंपनियों के लिए चिंता के विषय हैं और इसके लिए वे भारत को दोषी कम समझते हैं और डोनाल्ड ट्रम्प को ज्यादा दोषी मानते हैं। संकट में भी अवसर आता है, अवसर को देखने और आकलन की शक्ति होनी चाहिए।

वास्तव में ट्रम्प की टैरिफ चौधराहट का ही नमूना था और भारत को झुकाने और भारत पर चैंडराइट लादने का हथकंडा था। निशाना कहीं और था। निशाना रूस और ब्लादमीर पुतिन थे। पुतिन का यूक्रेन युद्ध इसके पीछे कारण था। भारत अपनी ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से ईंधन खरीद रहा था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस ने सरस्ता ईंधन बेचना शुरू कर दिया था। खासकर भारत को और भी सरस्ता ईंधन बेच रहा था। सरस्ते ईंधन खरीद कर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया ही इसके अलावा भारत ने अपने नागरिकों को राहत दिया। भारत के नागरिक ईंधन समस्याओं से प्रसित रहे हैं, महंगे ईंधन का अर्थ नागरिकों के सुंदर भविष्य पर प्रहार करना। महंगे ईंधन से महंगाई बढ़ती है और जेब खाली होती है। भारत ने सरस्ते तेल खरीद कर बेचा भी। अमेरिका और यूरोप को यह स्वीकार नहीं हुआ कि उनके हितों को बलि देकर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और राष्ट्रीय वचत करे। सरस्ते तेल को बेचकर पैसे कमाये। अमेरिका ने पहले भारत को धमकाया, डराया और प्रतिबंधों का प्रहार किया। लेकिन भारत डरने का कार्य नहीं किया। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को निर्यतित करने के लिए टैरिफ युद्ध का सहारा लिया और पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। भारत ने टैरिफ युद्ध के सामने भी समर्पण करने से इनकार कर दिया और रूस के साथ ईंधन खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने इधर रूस के साथ अपनी आर्थिक और सामरिक दोस्ती भी प्रगाढ़ की है, जिसकी चिंता अमेरिकी कूटनीतिज्ञ को हो रही है। भारत अब ऐसी स्थिति में है कि वह अमेरिकी टैरिफ हथकंडे के सामने बिना झुके सौदेबाजी-समझौते बाजी कर सकता है। क्योंकि ट्रम्प टैरिफ पूरी तरह निष्प्रभावी हो गया है। अमेरिका के सामने लाभ लेने की संभावनाएं बची नहीं हैं। इसलिए टैरिफ के प्रश्न पर अमेरिका और भारत के बीच कोई समझौता और सहमति बनती है तो फिर भारत के हित सुरक्षित ही होंगे। ऐसी परिस्थितियां भारत की आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक महाशक्ति होने के संकेत देती हैं।

